

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-51
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन

51. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) प्राथमिक स्तर पर डिजिटल पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए पंजाब राज्य से चयनित विश्वविद्यालयों के नाम क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी- 2020) डिजिटल शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की कल्पना करती है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए उच्च-गुणवत्ता, सुलभ और समान शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह नीति शिक्षा प्रणाली में डिजिटल उपकरणों, संसाधनों और प्लेटफार्मों के एकीकरण को बढ़ावा देती है।

एनईपी 2020 के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और वहनीयता में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय एक व्यापक योजना “सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन” (एनएमईआईसीटी) को कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित सहित कई कार्यकलापों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है:

i. **स्वयम** - स्वयम का उद्देश्य व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में छात्रों, पेशेवरों और आजीवन शिक्षार्थियों के लिए समावेशी अधिगम अवसरों को बढ़ावा मिलता है। स्वयम ने अपनी स्थापना के बाद से 4.63 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ 3500 से अधिक

अनूठे पाठ्यक्रम पेश किए हैं। पंजाब राज्य में स्वयम कोर्स क्रेडिट अपनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची अनुलग्नक I में दी गई है, जिसे https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है।

ii. **स्वयम प्रभा:** स्वयम प्रभा 48 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना है। ये चैनल पंजाब राज्य सहित देश भर के सभी शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं तथा डीडी फ्री डिश और इंटरनेट अनुप्रयोग के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। दिनांक 21 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, 1.5 लाख से अधिक अद्वितीय शैक्षिक वीडियो व्याख्यान हैं, जिनका कुल देखने का समय 92,000 घंटे से अधिक है।

iii. **स्वयम प्लस:** शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने अग्रणी उद्योग भागीदारों के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों के बीच रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। आज की स्थिति के अनुसार, प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के साथ 55 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाएँ, बैंकिंग, वित्त सेवाएँ और बीमा आदि सहित उभरते क्षेत्रों से 322 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। दिनांक 21 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म पर नामांकित शिक्षार्थियों की कुल संख्या 1.2 लाख से अधिक है।

iv. **साथी:** यह प्लेटफॉर्म देश भर के सभी छात्रों/शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, एसएससी, आईसीएआर, सीयूईटी और आईबीपीएस आदि के लिए गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है।

इस विषय-वस्तु को प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया गया है, जो छात्रों/शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। यह प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक वीडियो व्याख्यान, 80,000+ समस्याएँ, मॉक टेस्ट, एक एआई चैटबॉट प्रदान करता है और जेईई, नीट, एसएससी आदि के उम्मीदवारों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

V. **समर्थ** – सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार डिजिटल परिसर बनाने के लिए समर्थ ईआरपी समाधान शुरू किया है। समर्थ का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एक ही मंच पर 40 से अधिक मॉड्यूल वाले 9 पैकेजों के साथ पूरी तरह से प्रबंधित, क्लाउड-आधारित, व्यापक ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) समाधान प्रदान करना है। दिनांक 21 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, पंजाब के 13 विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों ने अनुलग्नक II में दिए गए प्लेटफॉर्म को अपना लिया है, जिसे https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है।
